

दृष्टि व्यक्ति कुछ वस्तुएं चाहता है,
विलासी बहुत सी और लालची सभी वस्तुएं
चाहता है -अज्ञात

“ऑनलाइन”

सुंजवान सैन्य शिविर पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मरना निश्चित था। पैरा कमांडो और गरु डू कमांडो ने जिस ढंग से आत्मघाती दस्ते का मुकाबला किया उसकी पूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। आतंकियों के निशाने पर आवासीय परिसर एवं आयुध भंडार थे। यह सैन्य ऑपरेशन की सफलता मानी जाएगी कि आतंकवादी इसमें से किसी में सफल नहीं हुए। आवासीय परिसरों से लोगों को बाहर निकाल लिया गया और आयुध भंडार सुरक्षित बच गया। किंतु यह हमला जम्मू-कश्मीर के सैन्य स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। इतने सुरक्षित सैन्य बिगेड का सुरक्षा धेरा तोड़कर घुस जाना कोई सामान्य बात नहीं है। आखिर वे किस तरह चाहरदीवारी के नीचे सेंधें बनाकर घुसने में कामयाब हो गए? सुबह के समय सैन्य वर्दी में हथियार लिये दौड़ते आतंकवादियों को सैर करने वाले ने टोका और वे गोलीबारी करने लगे। आतंकवादियों का अंत करने और शिविर को सुरक्षित घोषित करने में जितना समय लग रहा है, उससे अंदाजा लग जाता है कि उह्नोंने कितना सोच-समझकर षट्यूंत्र रचा था। इस हमले से जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आगर सैन्य अड़े सुरक्षित नहीं हैं तो पिछ हमारी सुरक्षा कौन करेगा? वास्तव में इस हमले ने राज्य के साथ देश के सभी ऐसे सैन्य शिविरों की सुरक्षा की नये सिरे से मूल्यांकन कर उसमें आवश्यक सुधार करना अपरिहार्य कर दिया है। इसके कुछ ही दिनों पहले आतंकवादियों ने अस्पताल परिसर के बाहर हमला करके जेल से स्वास्य जांच के लिए लाए गए लश्कर-ए-तैयबा के एक खूंखार आतंकवादी को छुड़ा लिया। दोनों घटनाओं में सुरक्षा चूक साफ-साफ नजर आ रहा है। थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी जम्मू पृष्ठुंच गए हैं। जाहिर है, वे ऑपरेशन के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी कर रहे होंगे। ऐसे समय पूरे देश के एकजुट होने की आवश्यकता होती है। जम्मू-कश्मीर विधान सभा में कुछ सदस्यों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाकर यही दिखाने का प्रयास किया था। लेकिन विधान सभा के अंदर नेशनल कांफ्रेंस के एक वरिष्ठ विधायक ने जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और बाद में भी अपने बयान पर कायम रहा, वह सत्र करने वाला है। आश्र्वय है कि न तो पार्टी ने उस विधायक को पार्टी से निकाला, न कोई कार्रवाई ही हुई। कायदे से उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी ताकि दूसरे आस्तीन के सांगों को सबक मिलता।

मौद्रिक नीति समीक्षा

अंदाजा तो पहले से होने लगा है कि जैसे-जैसे चुनावी वेला करीब आती जाएगी, राजनैतिक तल्खी तेज होती जाएगी। लेकिन लगातार नये-नये मुहावरे और विश्लेषणों की तलाश में मर्यादाएं भी छूटी जाएंगी, यह उम्मीद शायद नहीं की जा सकती। कर्नाटक की चुनावी सभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर तो आरोप लगाए ही, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर “रियर मिरर ब्यू” यानी पीछे देखु नजरिए का आरोप भी मढ़ा। उसके पहले बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पिछली घटनाओं और प्रकरणों का जिक्र करके कांग्रेस पर तीखा हमला किया था। असल में दांव इतने ऊंचे हैं कि दोनों तरफ उतावलापन नजर आने लगा है। इस उतावलेपन से तल्खी लगातार बढ़ेगी और इससे राजनैतिक सहमतियों की जगह लगातार सिकुड़ी जाएगी, जो लोकतंत्र के स्वस्थ अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। ऐसी तल्खी पहले भी देखने को मिली हैं लेकिन इतनी मर्यादा रखी जाती रही है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां भी सिर्फ मुद्दों को लेकर हों, किसी तरह की छोटाकशी न हो। यह हमेसा ध्यान रखना होगा कि मकसद सिर्फ येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतना भर न हो। दरअसल, चुनाव मुद्दों के प्रति जनता में जागरूकता लाने और सियासी फलक को भविष्य की दिशा में मोड़ने का मौका भी होता है। समय के साथ जो नई चुनौतियां उभरती हैं इसलिए चुनाव को लोकतंत्र को समुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करना ही असली उद्देश्य होना चाहिए। आर्थिक प्रगति के लिए भी जरूरी है कि सियासत ऐसी सहमति के बिंदुओं पर जाकर खड़ी हो। तभी हम सभी विकल्पों को तौलते हुए खुशहाली के रास्ते पर चल सकेंगे। विकास प्रक्रिया में यह देखना भी जरूरी है कि वह समावेशी हो और सभी को उसका कमोबेश समान लाभ मिले। आज देश आर्थिक बदहाली के जिस कगार पर खड़ा है, उसमें यह सबसे जरूरी बन गया है कि विकास के तरीके पर विचार किया जाए। इसके लिए यह भी जरूरी है कि एक राजनैतिक सहमति का बिंदु तैयार हो, जहां से समस्याओं पर गंभीरता से विचार हो सके। आशा की जानी चाहिए कि नेता और राजनैतिक पार्टियों में इस लोतांत्रिक तकाजे का एहसास गहराए।

सत्संग

शिव भक्त

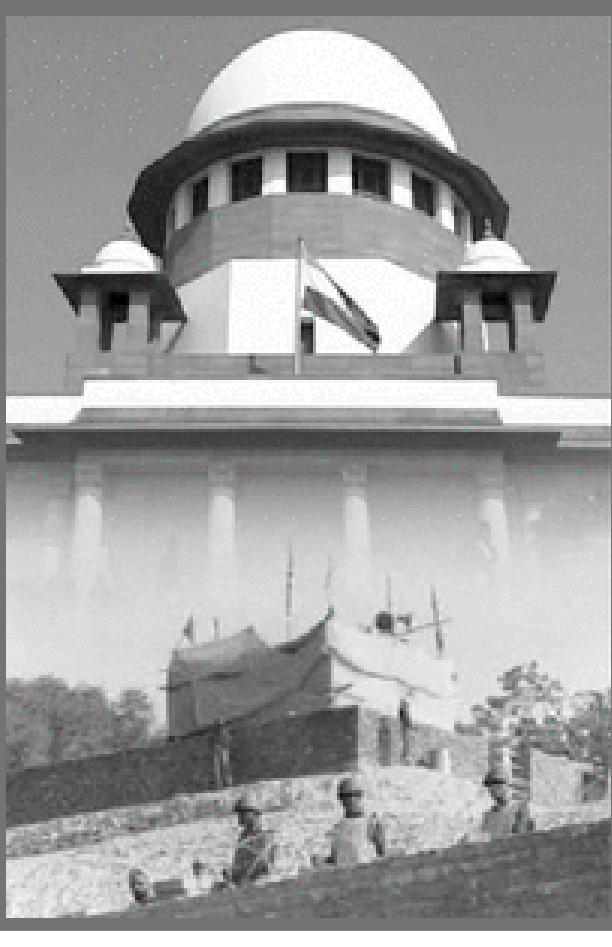
शक्तियोग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्धभक्त न तो स्वर्गलोग जाना चाहता है और न ब्रह्मज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्धभक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्यचरितामृत में शुद्धभक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक ओर जहां ज्ञानयोगी, कर्मयोगी या हठयोगी का अपना-अपना स्वार्थ रहता है वहाँ पूर्णभक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्धभक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश और अवतार हैं। यथा राम तथा नृसिंह। जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमाभक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समर्प्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अध्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्तियोग अत्यंत सरल शुद्ध और सुगम है। इसका शुभारंभ हरेकृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सब पर कृपालु हैं किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं, वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं। जैसा कि वेदों (कठोपनिषद) में कहा गया है— येमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम अर्थात् जिसने पूरी तह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। गीता में भी कहा गया है— ददामि बुद्धियोगं तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें भगवद्वाम में प्राप्त कर सकें। शुद्धभक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश और काल का विचार किये बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में-जहां भगवान रह चुके हैं, रहना चाहिए किंतु शुद्धभक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था—आप जहां भी हैं हे प्रभु! वहाँ वृदावन है।

“बेरोजगारों का हख”

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का समापन जिस तरीके से किया, उसकी मिसाल शायद ही मिलेगी। उपलब्धियां गिनाई, मगर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को कोसते हुए। विपक्ष के सवालों के जवाब देने से बचते हुए उन्होंने कांग्रेस पर ही कई सवाल दागे। बेरोजगारी, एनपीए जैसे मुद्दे पर भी पीएम मोदी उल्टे कांग्रेस से सवाल करते दिखे। राजनीतिक जगत में बेहतरीन वक्ता के रूप में जो जगह नरेन्द्र मोदी ने करोड़ों लोगों के दिलों में बनाई है, यह भाषण उससे हटकर नजर आया। हालांकि, नरेन्द्र मोदी नहीं चाहेंगे कि चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बने, लेकिन इसे मुद्दा बनने का आधार भी तैयार हो गया है।

सतीश पेडणोकर

अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई पर पूरे देश की नजर है। इसलिए वहां से जो भी खबरें आतीं हैं वह सुर्खियां बनतीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी की सुनवाई के दौरान कहा कि वह इसे सिर्फ भूमि विवाद के रूप में देख रही है। यानी वह केवल इस बात की सुनवाई करेगी कि 2.77 एकड़ की जो विवादित भूमि है उस पर किसका स्वामित्व बनता है? न्यायालय की इस टिप्पणी को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। लेकिन इस टिप्पणी को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। हमारी भावनाएं क्या हैं, हमारी आस्था क्या कहती हैं.. आदि आधार पर न्यायालय न सुनवाई कर सकती है न कोई फैसला दे सकती है। न्यायालय को ठीक सबूतों और तथ्यों के आधार पर फैसला करना होता है। इसलिए न्यायालय ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल स्वाभाविक है। न्यायालय के अंदर मामला ही यही है कि उस भूमि पर आखिर अधिकार किसका है? इसके अभी तीन पक्षकार हैं, निर्मीती अखाड़ा, रामलला विराजमान एवं सुनी वक्फ बोर्ड। शिया वक्फबोर्ड की ओर से हाल में उच्चतम न्यायालय में यह दावा दायर किया गया है कि उसमें सुनी वक्फ बोर्ड का नहीं उनका हक बनता है। न्यायालय इस पर क्या फैसला देती है यह आगे की बात है। लेकिन इस समय तीन ही पक्षकार हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इन्हीं तीन पक्षकारों की सुनवाई करके फैसला दिया था। इसलिए न्यायालय के इस कथन को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। हम मानते हैं कि अयोध्या विवाद से करोड़ों की भावनाएं जुड़ीं हैं, पर न्यायालय के सामने जो 20 याचिकाएं इससे संबंधित लंबित हैं, जिनका संज्ञान लिया गया है, उन सारे में विवादास्पद भूमि पर दावा ही तो किया गया है। तो फिर फैसला दूसरी किसी बात का कैसे हो सकता है? हालांकि न्यायालय ने जो कहा है, उसको सीमित अर्थ में नहीं लिया जाए। इसका यह निष्कर्ष न निकाला जाए कि जो ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, या प्राचीन ग्रंथों से संबंधी सबूत हैं, उनको न्यायालय ने अपनी सुनवाई की परिधि से बाहर कर दिया है। बाजाब्ला सुनवाई आरंभ करने में देरी ही इसलिए हो रही है क्योंकि उच्च न्यायालय ऐसा-ऐसा दर्जा पर्याप्त नहीं करता है जो अपनी ग्रंथों को पाया है। उच्चायालय गया, उनके संबंधित अंशों का भी अनुवाद हुआ है। ये ग्रंथ, संस्कृत, पाली, फारसी, अरबी, उर्दू आदि भाषाओं में हैं। कहा गया है कि केवल रामचरित मानस और श्रीमद्भगवत् गीता के आवश्यक अंशों का अनुवाद होना शेष है। इसलिए यह आशंका भी किसी को नहीं होनी चाहिए कि उस स्थल से संबंधित बातें जो उनके धार्मिक ग्रंथों या अन्य ऐतिहासिक मान्यता वाली पुस्तकों में किया गया है वे शायद बाहर हो जाएंगे। वास्तव में इससे संबंधित साक्ष्य एवं तय जितने ज्यादा हैं, उनके आयाम जितने विस्तृत हैं उन्हीं से यह मामला ज्यादा जटिल हो जाता है। कुल 524 दस्तावेजों में से 504 के अनुवाद उच्चतम न्यायालय में दाखिल हो चुके हैं। जिन पुस्तकों की बात हमने की, उनसे संबंधित नौ हजार पृष्ठ हैं जिनका अनुवाद किया जाना था। इसके अलावा 90 हजार पृष्ठों में 87 गवाहों के बयान दर्ज हैं। जो सूचना है इनका अनुवाद और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट भी दाखिल हो चुका है। यह उम्मीद की जा सकती है कि 14 मार्च को होने वाली अगली समाप्ति तक पर्याप्त दर्जे आएंगे।



सुनवाई तक सरे दस्तावेज सभी पक्षों को अनुवाद सहित उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद न्यायालय अपनी सुविधानुसार नियमित सुनवाई कर सकेगा। शायद प्रतिदिन सुनवाई संभव न हो, क्योंकि जब यह मांग न्यायालय के समक्ष रखी गई तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा कि यह मामला महत्वपूर्ण है और इसकी हमें चिंता है लेकिन न्यायालय के सामने 700 मामले ऐसे हैं, जिनकी सुनवाई के लिए याची गुहार कर रहे हैं। यह बात ठीक है कि देश इस लंबे विवाद का शीघ्र समाधान चाहता है। यह विवाद देश में सांप्रदायिक तनाव और आपसी दुर्भावना पैदा होने का कारण बना है। इसलिए देश के हित में सितम्बर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया। उसने हालांकि इसे जमीन का विवाद नहीं माना था लेकिन जमीन को तीनों पक्षकारों के बीच बराबर बांट दिया। उसके बाद भी बातचीत कर समाधान निकाला जा सकता था। किंतु ऐसा नहीं हुआ तो इसके गहरे कारणों को हमें समझना होगा। सभी पक्ष उच्चतम न्यायालय गए और वे घोषणा कर रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा वह हमें मंजूर होगा। तो उच्चतम न्यायालय एवं उसे लेकर पक्षकारों की टिप्पणियां उम्मीद जगाती हैं कि अयोध्या विवाद का समाधान शायद हो जाएगा। न्यायालय की अभी तक की सारी टिप्पणियां इसी ओर इशारा कर रही हैं।

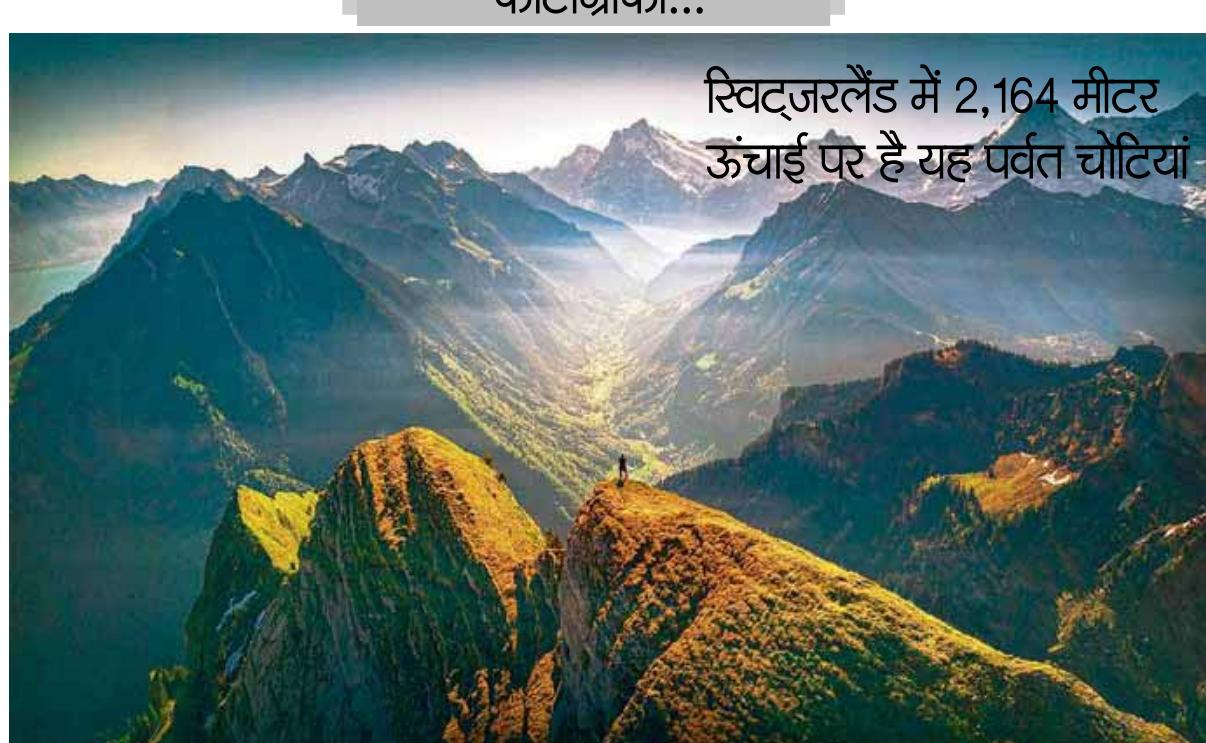
चलते चलते

‘धरती पर गंदगी’

सेना से अलग राह चुनने वाले नेता राज ठाकरे अब व्यक्ति से विचार बनते जा रहे हैं। उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनकी हिंसा की राजनीति की झालक गोवा सरकार में मंत्री विजय सरदेसाई के बयानों में मिली। सरदेसाई गोवा में गंदगी पर बात परते हुए इतना आगे बढ़ गए कि उत्तर भारतीयों को “धरती पर गंदगी” की संज्ञा दे दी। उत्तर भारतीयों को “सस्ते पर्यटकों” की श्रेणी में रखते हुए गोवा को “हरियाणा” ना बनाने की बात कह डाली। गोवा फॉर्मेंड पार्टी के अध्यक्ष सरदेसाई के बयान में ईमानदारी कम, एक क्षेत्रीय दल के विभाजनकारी राजनीतिक एजेंडा की बूज्यादा ज्यादा आ रही है। दरअसल, विजय सरदेसाई का बयान विशिष्ट होने की भावना से ज्यादा ग्रस्त है, जिसमें वे और राज्यों की तुलना में गोवा को ज्यादा विकसित सरदेसाई गोवा में गंदगी पर बात परते हुए इतना आगे बढ़ गए कि उत्तर भारतीयों को “धरती पर गंदगी” की संज्ञा दे दी। उत्तर भारतीयों को “सस्ते पर्यटकों” की श्रेणी में रखते हुए गोवा को “हरियाणा” ना बनाने की बात कह डाली। बताते और दिखाते हैं। बयान में गोवा के विकास का गौरव कम उत्तर भारतीय राज्यों को उनके पिछड़ेपन का बोध करना ज्यादा दिखता है। एक तरफ उनकी स्वीकृति की पर्यटन के लिए गोवा उत्तर भारतीयों पर निर्भर है वहीं “धरती पर गंदगी” उनके दोहरेपन को भी परिलक्षित करती है। लेकिन सरदेसाई यह भूल जाते हैं कि खनन माफिया ने गोवा के पर्यावरण का क्या हाल कर दिया, मादक पदार्थों का कारोबार किसी से छिपा नहीं है, जो कथित तौर पर उनके “महंगे पर्यटकों” के इर्द-गिर्द पनपता रहा है। अपवाद हर समाज-संस्कृति में होते हैं, लेकिन सभी को एक ही चर्शमे से देखना; दुर्भावना से ज्यादा नहीं। इस दिक्कियानुसूती विचार से एक क्षेत्र के लोगों का दूसरे क्षेत्र के प्रति पूर्वग्रहों को ताकत मिलती है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए दिए जाने वाले बयान देश को कहीं से मजबूती नहीं प्रदान करते। बेहतर तो यह होता की राष्ट्रवाद की झण्डाबरदार भाजपा के मुख्यमंत्री अपने इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाते। किंतु ऐसा नहीं हुआ। पर्यटक स्वच्छता को गंभीरता से लें, इसके लिए गोवा सरकार को सतही बयानबाजी से इतर जागरूरता कार्यक्रम कराने की दरकार है। ऑनस्पॉट सफाई के वर्कशाप आयोजित कर भी साफ-सफाई की बात कही जा सकती है। जहां तक हरियाणा की बात है, इसने अन्य उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में बेहतर तरकी हासिल की है। दूसरा कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए अपना सामाजिक व्यवहार दुरुस्त करने की जरूरत है, सिर्फ विरोध से छाव नहीं सुधरेगी।

फोटोग्राफी...

स्विट्जरलैंड में 2,164 मीटर
ऊँचाई पर है यह पर्वत चोटियां



यह फोटो स्विट्जरलैंड में बर्न शहर के पास 'बर्नर ओबरलैंड' का है, जिसे ग्रीनलैंड के फोटोग्राफर मैक्स राइव ने किलक किया है। वे यहाँ स्कूल के दिनों में आए थे और तभी उन्होंने विचार किया था कि वे यहाँ दोबारा आएंगे। आज वे कहते हैं, मेरा सौंभाग्य है कि मैं फिर यहाँ आ सका। यहाँ एल्प्स पर्वत श्रृंखला की खूबसूरती अद्भुत है। यहाँ की सभी जगहें बैसी ही हैं, लेकिन इस बार पहुँचने का अनुभव सबसे यादगार रहा। 2,164 मीटर की ऊँचाई वाली इस जगह पर थुन झील भी है, जो पर्वतों से आने वाले पानी से बनी है। मैक्स ने बताया कि शाम होते ही यहाँ अक्सर इतने अधिक बादल एकत्र हो जाते हैं कि पर्वत चोटियां नजर नहीं आतीं इसीलिए उन्होंने सुर्योदय के बाद यह

एकत्र हा जात ह कि पवत चाटया नजर न
फोटो क्लिक किया। facebook.com

ਨਵੀਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਏ

आधुनिक दुनिया में कारें विकास का प्रतीक बन गई हैं। दो साल पहले (2016 में) आयकर विभाग ने टैक्स चुकाने वालों का एक अंकड़ा पेश कर एक तुलना की थी। उसने कहा था कि देश में सिर्फ 24.4 लाख करदाताओं ने अपनी सालाना आय दस लाख से ज्यादा बताई, जबकि हर साल यहाँ 25 लाख कारें खरीदी जा रही हैं। खास बात यह है कि इनमें से करीब 35 हजार कारें लग्जरी गाड़ियों में आती हैं, जिनकी कीमत दस लाख से ज्यादा होती है। सवाल यह उठाया गया है कि जब आमदनी नहीं है तो आखिर महंगी कारें खरीदने वाले लोग कौन हैं? बहरहाल, दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में आयोजित देश के 14वें ऑटो एक्सपो में देश-विदेश की ज्यादातर कार कंपनियां इस हसरत के साथ भागीदारी कर रही हैं कि कार बाजार में होने वाला उछल उनकी हालत ही नहीं सुधारेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी प्राण पूँक देगा, भले ही कार खरीदने वाले लोग इनकम टैक्स ना दें। इधर, पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली और गुडगांव आदि शहरों में अपनाए गए सम-विषम (ऑड-ईवन) के फॉर्मूले से घबराई कार कंपनियों को डर है कि कहीं ऐसे नुस्खे ज्यादा राज्यों में या पूरे देश में न फैल जाएं। हमारे देश में यह तकरीबन सांचित हो चुका है कि मिडिल क्लास भी कार के मामले में दिखावे को अहमियत देता है, न कि जरूरत को। वे लोग भी कार खरीदते हैं, जिनके घर के पड़ोस में आसानी से सार्वजनिक बस-ऑटो से लेकर मेट्रो तक के विकल्प उपलब्ध हैं। इधर पिछले दो-तीन वर्षों से कंपनियां कारों की विक्री में हुई थोड़ी-बहुत कमी से घबराई हुई हैं। यही वजह है कि कार कंपनियां ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो जैसे आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और यह सपना देख रही है कि इस देश की विशाल मध्यवर्गीय आवादी, जिसकी खरीद क्षमता में पिछले एक-डेढ़ दशकों में काफी इजाफा हुआ है, कारों पर मेहरबान होगी और कार कंपनियों को मालामाल कर देगी। अलबत्ता ज्यादातर परिवारों के लिए महंगी-से-महंगी कारें स्टेटस सिंबल जरूर हैं लेकिन ध्यान रहे कि स्टेटस बढ़ाने वाली कारें किसी समस्या का समाधान नहीं सुझाती हैं, जबकि हमारे देश में किसी भी ऐसे उपक्रम का पहला उद्देश्य बड़ी दिक्कतों को हल निकालना होना चाहिए। यूं देश में एक तबका ऐसा भी है, जो कारों को जरूरी कमेडिटी (साधन) मानता है। आज की पीढ़ी कहीं आने-जाने के लिए बस, मेट्रो या ऑटो-टैक्सी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि वह निजी ट्रांसपोर्ट की हिमायती है। कारों को समस्या के रूप में देखने की नीति या समझ के विरोधियों का एक अलग मत है। वे कहते हैं कि समस्या कारें नहीं, बल्कि सड़कों व ट्रांसपोर्ट के दूसरे इंतजामों की है। हमारे देश में ज्यादातर सड़कों कारों के हिसाब से डिजाइन नहीं की गई। पार्किंग के समुचित प्रबंध नहीं किए। ऐसी ही समस्याओं के चलते कारें किसी समस्या का समाधान बनने की बजाय खुद में एक समस्या बन गई हैं। पर्यावरणविद् सवाल उठाते हैं कि आखिर देश में कारों की जरूरत ही क्यों होनी चाहिए, जबकि सार्वजनिक परिवहन पण्याली को बेहतर करके लोगों की ट्रांसपोर्ट संबंधी जरूरतों का आसानी से हल निकाला जा सकता है। देश में आप जितनी चाहें उतनी निजी कारें खरीद सकते हैं, चला सकते हैं। मगर इसके विकल्प के रूप में जो सार्वजनिक परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, वह नदारद है। जैसे दिल्ली में कुल ट्रैफिक का 75 प्रतिशत हिस्सा निजी कारों का है लेकिन उनसे यात्रा की 20 प्रतिशत से भी कम जरूरत पूरी होती है। यह हालत तब है जब इस शहर के केवल 30 प्रतिशत परिवारों के पास कार की सुविधा है। ऐसे में कारों का अंधाधुंध उत्पादन और खरीद ट्रैफिक और प्रदूषण का क्या हाल करेगा, इस बारे में विचार ही किया जाना चाहिए।

